रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 1995/वैशाख 5, 1917
No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 1995/VAISAKHA 5, 1917

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1995

सा.का.नि. 361(अ).—अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त संवर्ग) नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं, अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के लिए एतद्द्वारा नियमानुसार एक संयुक्त संवर्ग प्राधिकारी का गठन करती है:—

"1. सचिव, गृह मंत्रालय (भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

2. मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश

3. मुख्य सचिव, गोवा

4. मुख्य सचिव, मिजोरम

5. मुख्य सचिव, दिल्ली

6. वन महानिरीक्षक, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (भारतीय वन सेवा के लिए संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

7. संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र प्रभाग) गृह मंत्रालय (भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए संयोजक)/संयुक्त सचिव (प्रभारी भारतीय वन सेवा संवर्ग प्रबन्ध), पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (भारतीय वन सेवा के लिए संयोजक)"।

[सं. 11026/2/94-अ.भा. से.-II]
मधुमिता डी. मित्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पण.—अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त संवर्ग) नियम, 1972 दिनांक 11-1-1972 की अधिसूचना संख्या 13/4/71-अ.भा.से.-I द्वारा अधिसूचित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित क्षेत्रों का संयुक्त संवर्ग प्राधिकारी की अधिसूचना 3-4-89 की अधिसूचना सं. 13013/1/89-अ. भा. से. (1) तथा 11-12-1992 की सा.का.नि. 919 (अ) द्वारा विज्ञापित की गई थी।

## MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1995

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 4 of the All India Services (Joint Cadre) Rules, 1972, the Central Government in consultation with the Government of States concerned hereby constitutes the Joint Cadre Authority for the Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service Joint Cadres of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, as below :—

"1. Secretary, Ministry of Home Affairs (representing Union Territories in respect of the Indian Administrative Service and Indian Police Service)

2. Chief Secretary, Arunachal Pradesh

3. Chief Secretary, Goa

4. Chief Secretary, Mizoram

5. Chief Secretary, Delhi

6. Inspector General of Forests, Ministry of Environment and Forests (representing Union Territories in respect of the Indian Forest Service)

7. Joint Secretary (Union Territories Division) Ministry of Home Affairs (Convenor in respect of the Indian Administrative Service and Indian Police Service) |Joint Secretary (in charge of Indian Forest Service Cadre Management), Ministry of Environment and Forests (Convenor in respect of Indian Forest Service)".

[F. No. 11026|2|94-AIS(II)]

MADHUMITA D. MITRA, Desk Officer

NOTE :—The All India Service (Joint Cadre) Rules, 1972 were notified vide No. 13|4|71-AIS(I) dated 11-1-1972. The Joint Cadre Authority of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre was notified vide Notification No. 13013|1|89-AIS(I) dated 3-4-89 and GSR No. 919(E) dated 11-12-1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995